धर्मनिरपेक्षता कमजोरी नहीं, है हमारी ताकत- विभूति नारायण राय

शांति, शिक्षा एवं संघर्ष समाधान पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन

हिंदी विवि में आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए देशभर के प्रतिभागी

वर्धा, 21 सितम्बर, 2011; महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा व इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज एण्ड कॉनफ्लिक्ट रिजॉल्यूशन, मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में शांति, शिक्षा एवं संघर्ष समाधान विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय (21से 23 सितम्बर) राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कुलपति विभूति नारायण राय ने बुधवार को कहा कि जब देश आजाद हुआ था हम विभाजन होने में सांप्रदायिक दंगों में झुलस रहे थे। कहा जा रहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसी समय एक मजबूत नेतृत्व मिला- महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जैसे नेताओं का। इनका मानना था कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते हैं। इस देश की धर्मनिरपेक्षता रेनासां की उपज है। यह पंथनिरपेक्षता की बात करती है जिनका मानना है कि यहां की मुख्य धर्म, राजनीति को संचालित करेगी। सही अर्थों में धर्मनिरपेक्षता आजादी के उपरांत संविधान बनने के दौरान सन् 1947 से 1950ई. में लंबी बहसों के बाद आया। रेनासां के बाद चर्च और राज्य को अलग कर दिया गया। इसी तरह की भावनाएं व मूल्य हमारे संविधान में शामिल किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य का कर्तव्य होगा कि वह सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। लेकिन क्या वजह थी कि आजादी के 60-65 वर्षों के बाद भी हम उन कारणों की तलाश कर रहे हैं जिनकी वजह से सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं।

सांप्रदायिक दंगे जैसे संवेदनशील विषय पर शोध कर चुके गंभीर अध्येता विभूति नारायण राय ने कहा कि सन् 1947 में जब देश विभाजित हुआ। वह मनुष्य की स्मृति का

सबसे बड़ा विस्थापन था। दोनों विश्व युद्ध में जितने जानमाल की क्षति हुई थीं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान देश विभाजन के समय इस भारतीय महाद्वीप में हुआ। गांधी जी की हत्या के बाद छिटपुट झड़पों के बावजूद सांप्रदायिक दंगे रूक गए थे। 1961 ई. में जबलपुर में एक बड़ा दंगा हुआ, उसमें भारतीय राज्य की कमजोरियां दिखायी पड़ी । 1962 ई. में भारत-चीन युद्ध व 1965 ई. में भारत-पाक युद्ध हुआ। 1961 ई. से 2011 ई. तक के बड़े दंगों के इतिहास को देखें तो हम पाते हैं कि हर दंगे में राज्य-प्रशासन असफल होता दिखाई देता है। बाबासाहब आंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी में लंबी बहसों के उपरांत यह बात आयी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। राज्य प्रत्येक नागरिक को एक समान मानेगा। सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस विषय पर शोध करने के दौरान मैंने पाया कि दंगों में ज्यादा क्षति अल्पसंख्यकों की ही होती है। राज्य की संस्थाओं को चाहिए था कि वे दंगाईयों को सजा दिलवाएं, उनकी गिरफ्तारियां करें। लेकिन इस मामले में वे लगातार असफल होती दिखी। 1961 ई. से अबतक के सांप्रदायिक दंगों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि देश में धर्मनिरपेक्षता कमजोर हुई हैं। अगर जनमानस में वैज्ञानिक सोच विकसित किया जाता तो देश सांप्रदायिकता की आग में नहीं झुलसता।

मार्क्सवादी विचारधारा से सोचें तो हम पाते हैं कि एक आधार होता है और दूसरा सुपरस्क्ट्रचर। ये पश्चिम से आया सुपरस्क्ट्रचर लोकतंत्र, समाजवाद, समानता के दर्शन की बात करता है। हमें लगता है कि इसकी नींव कमजोर थीं। सुपरस्क्ट्रचर ने नींव को मजबूत नहीं किया। शिक्षा से लोगों को सेक्यूलर बनाया जा सकता था। लेकिन राजनीति करने वालों ने हमें सेक्यूलर बनने में मदद नहीं की। पाठ्यक्रमों में ज्यादातर स्त्री विरोधी और दलित विरोधी सामग्री थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू का नेतृत्व मिला, जो समाज को आगे बढ़ाने वालों में से एक थे। यूनाईटेड प्रोविसेंज का नाम क्या हो, इसपर बहस हुई, उसका नाम दिया गया-आर्यावत। पंडित नेहरू के हस्तक्षेप से उसका नाम उत्तरप्रदेश पड़ा।

आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे समाजवादी व्यक्ति को हराने के लिए अयोध्या में प्रचारित किया गया कि ये तो एक नास्तिक आदमी हैं और यह भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है, क्या भगवान के क्षेत्र में नास्तिक आदमी को जिताया जाएगा। आचार्य नरेन्द्र देव को हराया गया और बाबा राघवदास को जिताया गया। हमने सुपरस्क्ट्रचर द्वारा बेस को मजबूत करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। आजादी के समय हम उतने प्रोग्रेसिव नहीं हो पाए थे। एक समझदारी विकसित की जा सकती थी कि धर्म तो व्यक्तिगत मसला है और राज्य को धर्मनिरपेक्षता के साथ चलने दें। राज्य की जिम्मेदारी सभी के जानमाल की रक्षा की है न कि सिर्फ हिंदुओं की। चुनाव के दौरान नेहरू के विपक्षी गंगाजल की शपथ दिलाकर उनके खिलाफ चुनाव में प्रयासरत थे तो फिर नेहरू को दो-तीन चुनावी सभा को संबोधित करना पड़ा था। जनता ने पंडित नेहरू को जिताया।

1967-68 ई. तक पाठ्यपुस्कों में धर्मनिरपेक्षता को एक तरह से मूल्य के तौर पर लिया जाना था, लेकिन नहीं लिया गया। सारे ऑपरेशन के प्रयासों के बावजूद अगर हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। धर्म के नाम पर ही पाकिस्तान बना था, जो कि 1971 ई. में टूट गया। हमारे ही बीच में हिन्दुत्व लोग तर्क देते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो क्या हम धर्मनिरपेक्षता का ठेका ले रखे हैं। आप जिस दिन भारत को धर्म आधारित राज्य बना देंगे, देश टूट जाएगा।

लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, यह वो खाद है जिससे कि हम एक बने हुए हैं। हमारी एकता की ताकत का परिणाम है कि 1962 ई. के सिवाय हमारी एक इंच भी जमीन नहीं गयी। सिक्किम जैसा राज्य भी हमारे भूभाग में शामिल है। सांप्रदायिक दंगों को रोकने में राज्य की असफलता के कारण ही ऐसी कार्यशालाओं की जरूरत पड़ रही है। भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता के अलावा और कोई चारा नहीं है।

विश्वविद्यालय के डॉ.जाकिर हुसैन अध्ययन केन्द्र द्वारा हबीब तनवीर सभागार में आयोजित कार्यशाला के उदघाटन सत्र के दौरान बीज वक्तव्य देते हुए असगर अली इंजीनियर ने कहा कि धर्म और राजनीति को एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए। गांधी जी बहुत धार्मिक थे और वे धर्म को राजनीति से दूर रखते थे। हम मूल्य को भूल जाते हैं और बांकी धर्म के आडंबरों में उलझ जाते हैं। ऐसे में उन ताकतों को आसानी होती है जो धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष राज्य में सांप्रदायिकता ताकतों के खिलाफ पीस एक्टिविस्ट तैयार करें। हम कम्यूनल हार्मोनी के लिए कार्य करें न कि राजनीति के लिए। विश्वविद्यालय के

प्रतिकुलपति व डॉ.जाकिर हुसैन अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो.ए.अरविंदाक्षन ने स्वागत वक्तव्य दिया। कार्यशाला के संयोजक व रिसर्च एसोसिएट मिथिलेश कुमार ने मंच का संचालन किया।

प्रथम अकादमिक सत्र में शांति कार्यकर्ता नेहा ने समूह गतिविधियों का संचालन किया तथा असगर अली इंजीनियर ने धर्म, सभ्यता एवं अस्मिता की राजनीति विषय पर वक्तव्य दिया। तृतीय अकादमिक सत्र में भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के सदस्य शीतला सिंह ने सांप्रदायिकता एवं मीडिया विषय पर तथा असगर अली इंजीनियर ने भारत की एकरूपी/मिश्रित संस्कृति विषय पर विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर देशभर (गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र) के प्रतिभागी तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ.के.जी.खामरे, अतिथि लेखक सुरेश शर्मा सहित अध्यापक, कर्मी, शोधार्थी, विद्यार्थी तथा वर्धा के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

22 सितम्बर को अकादमिक सत्र के दौरान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज एण्ड कॉनफ्लिक्ट रिजॉल्यूशन, मुम्बई के निदेशक इरफान इंजीनियर जाति एवं सांप्रदायिकता तथा धर्मनिरपेक्षता एवं भारतीय संविधान विषय पर उदबोधन देंगे। कुलपति विभूति नारायण राय सांप्रदायिकता को कैसे समझे, स्त्री अध्ययन विभाग की प्रो.इलीना सेन सांप्रदायिकता एवं जेंडर तथा नेहा सांप्रदायिकता एवं जेंडर विषय पर वक्तव्य देंगी।

23 सितम्बर को शांति, शिक्षा का तात्पर्य विषय पर विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी फ्यूजी गुरूजी शांति अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो.मनोज कुमार शांति शिक्षा का तात्पर्य व शिक्षा से संघर्ष समाधान की ओर विषय पर प्रो.रामशरण जोशी तथा सांप्रदायिकता एवं पाठ्य-पुस्तकें विषय पर शांति कार्यकर्ता मानस रंजन उद्बोधन देंगे। समापन समारोह की अध्यक्षता कुलपति विभूति नारायण राय करेंगे। समापन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये जाने के उपरांत कुलसचिव डॉ.के.जी.खामरे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन होगा।

-अमित कुमार विश्वास